[श्री मधु लिमये]

मंत्री जी ने दिया था उस से अधिक, एक साल बीतने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने सदन को जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन का यह उल्लंघन होता है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस सदन को इस समय यह साफ साफ बताने के लिये तैयार हैं कि एक विशेष अवधि के अन्दर राजाओं का निजी कोष हम समाप्त करेंगे और उन में से जो कुछ ऐसे लोग हों जो कि इस को बन्द करने से बिल्कुल भूखों मर जायेंगे तो उन लोगों के लिये इन्तजाम करेंगे लेकिन बाकी सब लोगों का निजी कोष समाप्त करेंगे फलां फलां तारीख के अन्दर ? क्या इस तरह की वह घोषणा करेंगे? और हमारे जो नौजवान तुर्की लोग हैं, क्या वे इस के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। यह भी मैं जानना चाहूंगा ?

SHRI Y. B. CHAVAN: The hon. Member, Shri Madhu Limaye, appears to be very pleased with himself for the answer he gave in Yugoslavia. I have, certainliy, not changed my position. If at all any definite answer is there, that answer I am repeating again. In principle, Government has taken a decision to abolish privy purses and privileges. But at the same time, I cannot indicate any target date in this matter because these matters have to be tackled with patience and understanding.

श्री मधु लिमये : एक साल हो गया, आप कोई अवधि नहीं बतायेंगे ? अध्यक्ष महोदय, अगर कोई निश्चित तारीख नहीं तो दो, तीन या चार महीने की अवधि ही बतायें। आप कोई अवधि भी नहीं बतायेंगे और काम भी नहीं करेंगे।

MR. SPEAKER: That is all.

12.12 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE DEPUTY PRIME MINISTER

MR. SPEAKER: I have got notice of a privilege motion against the statement made by the Deputy Prime Minister signed by a number of Members, Shri Madhu Limaye, Shri S. M. Banerjee and so many others.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): Before that, may I draw your attention to an adjournment motion submitted to you about the strike resorted to by the press workers?

MR. SPEAKER: I have a number of adjournment motions, not one, with me. Some I am allowing; some I am not allowing. Only one can be allowed a day. I wanted to hear this also.

I had taken a tentative decision. Later on, it was argued by a number of hon. Members belonging to different parties. They came to me. Now, I want to hear them. One of them may try to tell me what the case is so that I can request the Deputy Prime Minister to give me facts before I take a decision.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे अपना फर्ज अदा करना पड़ रहा है। यह बहुत कटु कार्य है लेकिन आवश्यक है इसलिये मैं करने जा रहा हूं। आज उप-प्रधान मंत्री, सन्त सोदारजो के लिए कसौटी का क्षण है और इसलिये मैं चाहूंगा कि मैं जो सवाल आज उठाने जा रहा हूं उस का फैसला प्रिविलेजेज कमिटी के द्वारा हो। वह कमिटी इस सवाल के सभी पहलुओं पर सोचे और जो उस को अपना अन्तिम निर्णय देना हो वह दे। केवल बहुमत के आधार पर इस सवाल को टालने का या खत्म करने का प्रयास नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि 30 अप्रैल को और पहली मई को जब इस सदन में वित्त विधेयक पर बहस हो रही थी

तो मेरे एक दोस्त श्री उमानाथ और मैं ने अपने भाषणों के दौरान में कुछ आरोप किये थे जिन का सम्बन्ध उप-प्रधानमंत्री के बेटे और उन के निजी सचिव से था। निजी सचिव इन शब्दों पर मैं विशेष जोर देना चाहता हूं। तो ये जो आरोप किये गये वे कुछ निर्यात-व्यापार के बारे में जो एक करारनामा हुआ था, उस के बारे में थे। बैंक रेट जो लांक किया गया उसके बारे में थे। डिवीडेन्ड फीज के बारे में पिछले वर्ष भी गलत खबर छपवाई गई थी उस पर शेयर बाजार में 5 लाख रुपया कमाया गया, उस के बारे में थे। बम्बई में राधाकृष्ण रुइया का घर जो कि पूंजीपतियों का घर है उन के खिलाफ भ्रष्टाचार या टैक्स चोरी के जो आरोप थे, उन के बारे में भी थे। शुरू में जब कांग्रेस के लोग हल्ला करने लगे तो उप प्रधान मंत्री ने कहा था : . .

"May I appeal to my hon. friends to treat this with the contempt it deserves?"

पहले तो बिलकुल तुच्छता दिखाना चाहते थे लेकिन बाद में धीरे-धीरे मैदान में आए और उन्होंने एक दफा नहीं, तीन दफा इस सदन के सामने कहा है कि मेरा लड़का मेरा निजी सचिव बना है उस का किसी भी व्यापार से, कारोबार से या धंधे से सम्बन्ध नहीं रहा है। उन्हों ने 64 में मुझ से कहा कि आप की सेवा करना चाहता हूं। मैं ने उस को बुलाया क्योंकि उस वक्त मैं मंत्री नहीं था और किसी दूसरे निजी सचिव का खर्चा नहीं कर सकता था। मैं उन्हीं के शब्द रखना चाहता हूं। एक दफा वे कहते हैं :

"He is not in business; he has gone out of business."

उस के बाद जब भाषण देने के लिये उठे, तब कहते हैं :

"But before I deal with the criticism relating to the Finance Bill, I must in fairness to the House, to myself and to my son, give facts about what my hon. friend, Shri Umanath, referred to as an impropriety; if nothing more than that, the insinuation was much more than that, but he did not have the courage to make that insinuation explicitly."

इस तरह हमारी हिम्मत के बारे में भी इन्होंने संदेह प्रकट किया। फिर आगे वे कहते हैं :

"Even propriety is not contained in it. That is what I want to explain. Let him know that my son has given up business from the year 1964; not now. After I had gone out of the Ministry he wrote to me that he wanted to serve me and serve the public and 'now that I was out of the Ministry, nobody will be able to say anthying". Therefore he went out of business and joined me as my private secretary. I could not afford in those days any other private secretary and he was good enough to come and serve me as my private secretary and from that time he has continued to serve me as my private secretary, even today, but he is not borne on Government establishment. He is not paid by Government anything for that matter."

अध्यक्ष महोदय, उस के बाद आगे भी बहस चलती रही और उन्होंने हम लोगों के बारे में यह कहा कि हम लोग विकृत मनोवृत्ति के हैं, परवर्स मैनटेलिटी के हैं। उन्होंने मेरे बारे में कहा है कि मेरा डिजीज्ड माइन्ड है यानी रोगी मन है मेरा। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। . . . (व्यवधान) प्रिविलेज कमेटी से भागिये मत, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

आगे उप-प्रधान मंत्री जी कहते हैं,

"Let me tell my hon. friend that I have greater regard for proprieties than any one of them. I have made inquiries through the police against my son whenever some papers have come like that; I have not let it alone. And I am happy . . ."

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): On a point of order. You were pleased to ask one of the signatories to give reasons for referring it to the Privileges Committee. But he is making a big speech. I would like him to tell us the merits on which he wants that this question should be referred to the Privileges Committee.

MR. SPEAKER: It is not a question of any speech. After all, I have given permission to him to explain the facts. He is only reading from the statements, the facts and all that. Whether he is to take five minutes or six minutes may be left to me to decide. Meanwhile, I would request and appeal to Shri Sheo Narain and others not to interrupt, because they are thereby only lengthening the duration of his speech and they are not helping the debate. If they do not interrupt, perhaps the hon. Member will take only five or six minutes. But if they interrupt, he may take 10 to 15 minutes. If one Member shouts from one side, there are two or three reay to shout from the other side. Therefore, that does not help anybody. Shri Morarji Desai is here and he will give his reply. Naturally, it will help me to understand both the sides. After all, the whole thing may take just five or six minutes. I would appeal to both sides to hear calmly and then help the Chair to take a decision.

Shri Madhu Limaye may give only the facts.

श्री मधु लिमये : मैं और कोई दूसरी बात नहीं दे रहा हूं। डाक्युमेंट्स से ही, दस्तावेजों से ही कोट कर रहा हूं।

Mr. SPEAKER: Let him come to the point. He is only reading from the debates so far.

श्री मधु लिमये : आगे मोरारजी भाई कहते हैं :

"I have made enquiries through the police against my son whenever some papers have come like that. I have not let it alone, and I am happy that my son was always found miles away from any kind of these things. It was only some perverse people who were trying to circulate these rumours against him."

आगे चल कर जब आचार्य कृपालानी ने पूछा कि इतना समय आप क्यों दे रहे हैं। इन व्यक्तिगत बातों को ले कर तो आप ने कहा :

"It should be treated with the contempt that it deserves.".

इस पर मोरारजी भाई कहते हैं :

"I have suffered all along from this kind of calumny patently and I have treated it with contempt, but when I find it being repeated in my presence, I should have failed in my duty if I had not said something, and it is, thing, and it is, therefore, that I have said something.".

आगे वह कहते हैं :

'If they do not stop, does not matter. I have said what I had to say. Afterwards . . .".

उधर उन्हों ने एक हिन्दी कहावत को इस तरह कहा है :

"हाथी चलत अपनी चाल, कुत्ते भूंकत भुंकाव" यह उन का अनुवाद है, मेरा नहीं है।

"Afterwards, the elephant will go away and the dogs will go on barking.".

अध्यक्ष महोदय, हम को इन्होंने कुता कहा है, विकृत मनोवृत्ति का आदमी कहा हुआ है। रोगी मन है ऐसा कहा है। अब मैं यह साबित करना चाहता हूं कि हम लोग जो

उन के ऊपर आरोप कर रहे थे उन को वास्तविकता का आधार था या नहीं । बहुत सारी बातें हैं लेकिन जो दस्तावेज हैं जो मैं ने आप के सामने रखने की अनुमति मांगी थी, मैं टेबुल पर रखना चाहता हूं ताकि सब लोग उस को पढ़ें ।

अध्यक्ष महोदय, इन के बेटे और यह जो डोड़साल प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है उस का रिश्ता 1956 से है । यह जो समझौता है यह कोलेबोरेशन का है और यह 1956 में हुआ था । उस में उन को विभिन्न कामों के लिए कुछ कमीशन देने का वायदा इस करार में किया गया है। यह नौकरी सम्बंधी करार नहीं है। यह दी बोम्बे जनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, यह इन के बेटे की कम्पनी कहिये, फर्म कहिये, उस का और इन लोगों का करार हुआ है। डोड्साल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में और कान्ति भाई के बीच में हुआ और उस करार के अनुसार इन को कुछ कमीशन मिला । यह मैं आप की इजाजत से रखना चाहता हूं ।

फिर उस के बाद 1960 पर मैं आता हूं । यह करार नहीं है । यह जब किसी को नौकरी पर रक्खा जाता है तो जो पत्र दिया जाता है वह है. . .

MR. SPEAKER: Which year is that?

श्री मधु लिमये : नाइंथ डे आफ दिसम्बर, 1960। यह हुआ कमिशन एजेंसी के बारे में करार और यह नौकरी के बारे में है । इन को पत्र दिया गया कि आप को नौकरी पर रखा जा रहा है । उस के मुताबिक में भी इन को कुछ हिस्सा दिया गया था लेकिन उस में मैं नहीं जाना चाहता हूं । एक इस करार का अनुच्छेद 3(ए) जो है वह मैं पढ़ना चाहता हूं :

"A monthly salary of Rs. 1650 (Rupees One thousand six hundred and fifty only), payable on the last working day of each calendar month, subject to deduction of taxes the company shall be bound to deduct. After completion of twelve months of service the monthly salary shall be increased to Rs. 2050 (Rupees Two thousand and fifty only)".

यानी तनख्वाह 1650 रुपये से प्रारम्भ होती है । एक साल के बाद उन की मासिक तनख्वाह 2050 रुपये हो जाती है । उस के बाद एक परिपत्र भी जारी किया गया है कांति भाई के बारे में . . .

SHRI P. G. SEN (Purnea): Are we going into all those matters now? Let him come to the point.

श्री मधु लिमये : यह मैं एविडिकेट प्रमाणित कर के रख रहा हूं . . . . (व्यवधान)

श्री रवि राय (पुरी) : रूल्स आफ प्रोसीज्योर पढ़िये ।

श्री मधु लिमये : फिर एक परिपत्र है जो करार के बारे में कहा जाता है कि कांती भाई यह सारा काम करेंगे । क्या काम करेंगे (व्यवधान) सार्वजनिक क्षेत्र की या निजी क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन के बारे में यह अध्ययन करेंगे । कुछ उस के ठेके वगैरह दिलवाने का काम यह करेंगे । यह परिपत्र जारी किया गया और अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, उप प्रधान मंत्री के कथनानुसार 1964 में यह इन के निजी सचिव बने । किस तारीख को बने यह इन्होंने बताया नहीं है मान लो वह 31 दिसम्बर, 1964 के पहले बने या उसी दिन बने यह भी मैं मानने को तैयार हूं कि 1964 मे आखिरी दिन बने । इसलिये 1964 का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं । लेकिन इन के निजी सचिव बनने के बाद उपप्रधान मंत्री का कहना है, कि निजी सचिव बनने के बाद इन का अर्थात् कांती भाई का कोई कारोबार या धंधा नहीं रहा . . . .

MR. SPEAKER: This is all prior to that. The Deputy Prime Minister has already said that after 1964 he has no connection.

श्री मधु लिमये : मैं महत्वपूर्ण करार पर आ रहा हूं ।

MR. SPEAKER: What is the use of going to 1956 and 1958 now? Let him point out something after 1964.

श्री मधु लिमये : 64 मैं ने नहीं कहा । 66 मैं ने कहा । अगर गलती से बोल गया हूं तो माफी चाहता हूं । मैं 64 के पहले नहीं जा रहा हूं । मैं 31 दिसम्बर, 1964 के बाद की चर्चा कर रहा हूं । अभी जिस करार को पढ़ने जा रहा हूं वह 8 जुलाई, 1965 का है :

"An agreement made this eigth day of July, 1965 between DODSAL PRIVATE LIMITED, a company incorporated and registered under the Indian Companies Act, 1913 and having its registered office at Mafatlal House, Backbay Reclamation, Bombay—1, (hereinafter called 'the company') of the one part and Shri Kantilal Desai residing at 'Oceana', N. Subhas Road, Bombay-1, inhabitant of Bombay (hereinafter called 'the said Kantilal') of the other part."

मतलब यह हुआ कि निजी सचिव बनने के बाद यह एग्रीमेंट हुआ था ।

"Whereas the said Kantilal during his employment with the company has rendered very valuable services to the company . . ."

SHRI P. G. SEN: What are the charges against the Finance Minister? If there are charges against the Finance Minister, then we shall hear him. Why should we hear allegations against his son? Let him bring his charges against Shri Morarji Desai and then we shall hear him.

श्री मधु लिमये :

"Whereas the said Kantilal during his employment with the company has rendered very valuable services to the company . . .".

"हैज रैंडर्ड" कहा है "हैड रेंड" नहीं कहा । यह भी नोट किया जाये ।

"And whereas the board of directors of the company in appreciation of such valuable services decided to pay him as provided hereundef:—

NOW THESE PRESENTS WITNESSETH and it is hereby agreed as follows: . . .

MR. SPEAKER: For what?

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH (Parbhani): Does that document relate to existing services or past services?

MR. SPEAKER: He has come to the crux of the problem. That is why I am asking him to read it again. Let him hear calmly and understand what he is reading.

SHRI P. G. SEN: We are not going to hear anything against Kantilal here. We object to it.

श्री मधु लिमये : यह महत्वपूर्ण है

"The Company shall pay him Rs. 2,050 per calendar month subject to dedution of such taxes therefor as may be applicable for a period of three years with effect from 1st April 1965".

इस का मतलब है कि 1 अप्रैल, 1966 के बाद तीन साल तक यानी 31 मार्च, 1968 अर्थात् इस साल तक कांतिभाई को 2050 रु० मिलते थे, जो रकम 12 महीने के बाद 1960 के करार के तहत उन की तनखवाह थी । अगर कोई यह कहे कि पुरानी सेवा के लिये जैसे पैंशन दी जाती है वैसे यह दिया तो . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह तो चिट्ठी में है ।

श्री मधु लिमये : नहीं । वही तो मुझे साबित करना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी दस पन्द्रह साल की सेवा बाद जितनी उन की तनख्वाह होती है उतनी पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन इन को तीन चार साल सेवा के बाद, कहा जाता है कि सेवा की, जो उन की अधिक से अधिक तनख्वाह थी उतनी ही पेंशन दी जाती है । कि श्री मोरारजी देसाई यह कहेंगे कि डीडमान कम्पनी या किसी और कम्पनी के किसी कारोबार के साथ उन के बेटे का सम्बंध नहीं है । लेकिन इस दस्तावेज से साबित होता है कि उन का सम्बन्ध बरकरार रहा और जिस तरह वह पहले "काम" करते थे उसी तरह "काम" करते रहे । चूंकि वह उन के निजी सचिव थे इसलिये सारे सरकारी कागजात वगैरह वह देख सकते थे, और इस कारण मेरा निवेदन है कि वह कंपनी का "काम" करते रहे । यह दस्तावेज सही हैं । इन को यह काट नहीं सकते हैं ।

मेरा यह कहना है कि इस की जानकारी उन को थी, और उस के बावजूद उन्हों ने यहां पर गलतबयानी की और हमारे ऊपर लांछन लगाने का बहुत ही अनुचित ढंग से प्रयास किया क्या मतलब है कि जिस के बारे में पहले से ही इस तरह के आरोप लगाये जाते थे उन को ले कर ये हमें लांछन लगा रहे हैं । जब श्री मोरारजी देसाई मंत्री नहीं थे, उस वक्त भी कांग्रेस में उन का प्रभाव कम नहीं था । गुजरात सरकार हो या दूसरी सरकारें हो, उन के ऊपर जरूर उन का प्रभाव रहा है । 1965 के बाद भी तीन साल तक उन को यह तनख्वाह मिलती रही है और जब वह तनख्वाह खत्म हुई उस के तत्काल बाद उस फर्म के ऊपर छापे पड़े हैं । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि उन्हों ने 2050 रु० देने से इन्कार किया इस लिये 31 मार्च, के बाद यह जानकारी सरकार को दी गई और यह छापे मारे गये । लेकिन उस वक्त कांतिभाई को पता नहीं था कि सारे दस्तावेज मिल जायेंगे और यह सारा मामला सदन के सामने आयेगा ।

अब यह विशेषाधिकार भंग का मामला कैसे होता है इस के लिये हैं मैं दो तीन अथारिटीज दे कर अपनी बात खत्म करूंगा और जो सवाल है उस को सदन के सामने रक्खूंगा ।

आप मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस देखिये । उस का शीर्षक है : मिसलेडिंग दी हाउस ।

"*Misleading the House*: The House may treat the making of a deliberately misleading statement as a contempt. In 1963, the House resolved that in making a personal statement which contained words which he later admitted not to be true, a former member has been guilty of a grave contempt".

MR. SPEAKER: Admitted not to be true.

श्री मधु लिमये : अब ये कहें कि उन को इस की जानकारी नहीं थी । मैं यह साबित करना चाहता हूं कि उन को इस की जानकारी थी । क्योंकि 1956 से उन का इस फर्म के साथ सम्बन्ध था । पिछले दो साल की बात है जब मैं ने सुब्रह्मण्यम का मामला उठाया था तब आप के पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने निर्णय दिया था :

[श्री मधु लिमये]

"What we have to see here is this: Any incorrect statement made by a Minister cannot make any basis for a breach of privilege" . . .

क्योंकि यह हमेशा गलतबयानी करते रहते हैं ।

"It is only a deliberate lie, if it can be substantiated, that would certainly bring the offence within the meaning of breach of privilege".

तो उन्हो ने जान बूझ कर असत्य वचन या असत्य भाषण या गलतबयानी की है या नहीं, यह सवाल है ।

अब दस्तावेजों की बात आती है । जहां तक मुझे पता है, और मैंने जानने की कोशिश की है, यह सही दस्तावेज हैं और यह सही निकलें हैं । मैं आथेन्टिकेट करने के लिये तैयार हूं । अगर वह साबित करें कि यह गलत कागज है, तो मेरे खिलाफ कार्यवाही हो सकती है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस की उन को जानकारी थी और आप ने स्वयं कल मुझे बतलाया था कि वह "नहीं" नहीं कहते । लेकिन उन का इस के ऊपर भाष्य है इंटरप्रेटेशन है, कि इस का मतलब यह नहीं होता है कि यह तनख्वाह है, यह तो पेंशन है । अगर भाष्य का ही सवाल है क्योंकि उन को यह जानकारी थी कि यह सौदा हुआ है और यह दस्तावेज सही है तो सवाल रहता है कि इस का अर्थ क्या है ? तो अर्थ तय करने का जिम्मा सन्त मोरारजी अपने हाथ में न लें । इस सदन की एक कमेटी है । उस के सामने यह जाय । यह इस से डरते क्यों हैं ? कमेटी के सामने यह जाय और वह सारी बातों को देखें । कांतिभाई और डोडसाल कम्पनी में जो सम्बन्ध रहे हैं उन को वह देखे । उस के बाद वह जो निर्णय करेगी वह मुझे कबूल है । अगर समिति कहती है कि यह पेंशन है तो ठीक है. लेकिन अगर समिति की राय में यह तनख्वाह है, और उन का कहना है कि उन को कोई कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं है, यह सही नहीं है इस लिये इस में नैतिकता का सवाल जुड़ा हुआ है । आज भी मैं मांग करता हूं कि मोरारजी भाई अपना इस्तीफा दे दें और कमेटी के सामने मामला जाय । मोरारजी के इस्तीफा दिये बगैर काम नहीं चल सकता है । उस के बाद अगर कमेटी उन को निर्दोष मानती है तो वह फिर उप-प्रधान मंत्री बने, इस में मुझे कोई शिकायत नहीं है ।

मैं मांग करता हूं कि वह हटें और मामला कमेटी के सामने जाये ।

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): I can very well appreciate that my hon. friend Shri Madhu Limaye is smarting under some of the words that I used when I replied to him in the budget debate, and therefore, I can understand his attempt to take revenge or whatever it may be called.

श्री मधु लिमये : फिर वही कर रहे हैं । वह गाली दें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है ।

SHRI MORARJI DESAI: I did not interrupt my hon. friend when he went on using words like Sant Morarji this, that and the other. If he wants to call me Sant even in joke or satire, it is no concern of mine, I am not bothered. I have never claimed to be a Sant, therefore it does not matter to me.

Then on the question of the documents, there is no question of disowning them. They are legal registered documents on stamp paper, they are not secret agreements in any way. They are all formal legal agreements interpretable by courts and under the Arbitration Act.

SHRI RABI RAY: By the Privilege Committee.

SHRI MORARJI DESAI: Therefore, where is the question of disowning them? It does not require any interpretation from anybody. They are so obvious. Even the agreements are so obvious that they do not require any interpretation. Therefore, you, Sir, may judge as to what it means. It is for you to say whatever you want to say.

Of course, my hon. friend will be satisfied if I resign. I am not going to oblige him. That is the function of the Prime Minister. If she asks me, if she has any such idea in her mind, I would resign even before she asks. Therefore, that is not the question. I am only responsible to her in this matter.

श्री मधु लिमये : वह तो मैं जानता ही था । वह स्वेच्छा से नहीं करेंगे ।

SHRI MORARJI DESAI: If I feel I am guilty, I would do it immediately. I would not wait for his asking. Therefore, that is not the question. Because he thinks I am guilty I should accept myself as guilty, is the height of impudence. That is all that I can say.

Now, I would like to read out so that my hon. friend may not again try to find out some word here and there and then start some other motion.

The accusation is that I misled the House on 30th April, 1968 when I made the statement that my son had ceased connection with business in 1964. In support of the accusation the hon. Member, Shri Limaya, claims to be in possession of photostat copies of some Agreements which had been entered into between my son and Messrs. Dodsal Private Limited. These photostat copies have appeared in the *Blitz* issues of June 15 and June 29 with a ring of misleading insinuations which is so characteristic of that paper.

SHRI RABI RAY: You can file a defamation suit.

SHRI MORARJI DESAI: I do not believe in throwing stones in dirt. These documents are with me: therefore, it is not necessary for him to start with a very heroic statement that he was prepared to stand by it. I have got the originals here with me; if he wants to see them he could see them also. If he had asked me beforehand I would have given him the documents; he would not have had to take the trouble of going either to *Blitz* or some other sources. The facts are as follows:

Messrs. Dodsal Private Limited—an A.E.G. not an Indian concern at that time—engaged my son as a Commission Agent from December, 1956.

In December 1960 the concern employed him as the Director Sales on a salary plus commission as is the usual basis for salaried employees. the total of which from the second year of service was a little over Rs. 4,000 p.m. the salary part being Rs. 1,650 during the first 12 months Rs. 2,050 after one year. The rest was the result of the commission which he got in the year.

[Shri Morarji Desai]

Both these agreements were signed by the European Manager terminable on six months' notice. The agreement of December, 1960 remained in force until 31st March, 1965 inclusive of the period of notice. He however ceased to do any work after June, 1964 for this company.

The last agreement providing for terminal benefits with a monthly remuneration of Rs. 2,050, but no commission was for 3 years with effect from 1st April, 1965.

As the photostat copy would show, this agreement imposes no business obligation except that nothing regarding the transactions done during the period when my son was with the concern as an agent or in service would be disclosed. This is an obvious precaution and cannot be deemed to be business connection. The cessation of the commission fees which were substantial would establish that no business was expected during the period. The payment of terminal benefit is as stated in the Agreement for valuable services rendered. This is a business evaluation entirely within the judgement of the concern and the Hon. House would not expect me to go into the details of this and similar other transactions in the business world.

The last agreement which has been used to impugn my statement relates to a period when I was out of office. It is nothing but fanciful to state that my general standing in public life would have brought this about. So many of us including my Hon. friend, Shri Limaye, have standing and influence but I do hope that in equity they would be saved the imputation should some good things happen to their families.

I would not like to go into various wild and irresponsible thoughts built around this matter. I had drawn distinction between the role of my son as my Private Secretary when I was out of office, and as my personal private Secretary when he accompanied me on one or two official tours. No part of the cost was met by Government nor had my son access to official records. It is equally absurd on the one hand to connect the timing of the raid by the Enforcement Directorate with the cessation of the agreement and on the other to insinuate that the enquiry is being interfered with. The enquiry is proceeding accaccording to law and regular progress reports are being watched in the Directorate of Enforcement and the Ministry.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, जल्दी में निर्णय न दिजिये । यह मामला समिति के सामने जाना चाहिये ।

MR. SPEAKER: No further discussion about it. We have been discussing it not only here but in the Chamber and I had given an opportunity to hon. friends. It is not as if some off hand decision is being given here. If there is some difference of opinion, and some scrutiny is to be made it may be done. But we all of us have heard both of them. The statement about documents made by Shri Madhu Limaye is not denied by the Deputy Prime Minister (*Interruption.*) Order, order. I have given the maximum chance to Members here and inside my Chamber also. Some have asked me about it. If there is really any difference of opinion, that will be a matter for the Privileges Committee to go into. He may not agree with what has been said and he may say it is bad; you may not agree with what Shri Desai has said; you may say it is bad. But that is a thing which can be dealt with in a different way.

AN HON. MEMBER: Refer it to the Privileges Committee.

MR. SPEAKER: It is the House, which can take a decision; as Shri Desai put it, it is the Prime Minister, and it is for the Prime Minister and this House.

श्री मधु लिमये : क्या इंटरप्रेटेशन का निर्णय बहुमत से होगा ?

MR. SPEAKER: I have heard you in the Chamber, outside the Chamber and now here. My only point is this: if you do not agree with the view expressed by him, the Prime Minister or this House, that is one position. The Privileges Committee could go into it only if you do not agree with what Shri Desai has said or Shri Desai does not agree with what Shri Madhu Limaye has said. Then the Committee will have to go into it.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): There is disagreement.

MR. SPEAKER: There is no disagreement. Both of them agree.

SHRI S. M. BANERJEE: It is a question of interpretation. Who is going to interpret it? Which interpretation is correct? That is the matter.

MR. SPEAKER: I am on my legs now. I wanted to give them a fair chance. I told them also that this was my opinion. I said so in the Chamber also. Whatever it was, I thought it was my duty, sitting in the Chair, to give them a chance to place it before the whole House so that they will have a chance, and the Deputy Prime Minister also could clarify the whole case. I have given them the chance. You may agree with each other's point of view or not. There is no privilege as such to be referred to the Committee. Therefore, it is closed.

12.47 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annual Report of Indian Statistical Institute

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Indian Statistical Institute, Calcutta, for the year 1966-67. [*Placed in Library. See* No. LT-1396/68].

Government Resolution on National Policy on Education

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं श्री त्रिगुणसेन की तरफ से शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के बारे में दिनांक 24 जुलाई, 1968 के सरकारी संकल्प संख्या एफ 30-60-67 आई० यू० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[*Placed in Library. See* No. LT-1397/68].

Notifications under Navy Act

THE DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA):

(1) I beg to re-lay on the Table a copy each of the following Notifications under section 185 of the Navy Act, 1957:—

(i) The Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Regulations, 1968, published in Notification No. S.R.O. 3-E in Gazette of India dated the 30th March, 1968.

(ii) The Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Second Am-